

अध्याय 17: आंतरिक सुरक्षा — खतरे, (CAPF), खुफिया एजेंसियां एवं सुरक्षा प्रबंधन — शॉर्ट नोट्स

1. भारत की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख खतरे एवं प्रकृति	
खतरा / आयाम	विधिक व सुरक्षा स्वरूप एवं चुनौतियां
आतंकवाद (सीमा-पार व शहरी)	पाक-प्रायोजित आतंकवाद, कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुट, शहरी क्षेत्रों में स्लीपर सेल का जाल
वामपंथी उग्रवाद (LWE / नक्सलवाद)	माओवादी विचारधारा प्रेरित सशस्त्र विद्रोह; 31 मार्च 2026 तक सभी जिले (LWE) मुक्त घोषित (सुरक्षा + विकास मॉडल)
पूर्वोत्तर उग्रवाद	जातीय व उप-राष्ट्रीयता आधारित हथियारबंद गुट; शांति समझौतों ((NSCN), (ULFA) आदि) से निरंतर स्थिरता
सीमा-पार घुसपैठ व नाक़ो-आतंकवाद	ड्रोन के जरिए हथियार/ड्रग्स तस्करी (पंजाब, जम्मू सीमा); नशीले पदार्थों से आतंकी फंडिंग का सिंडिकेट
साइबर व संकर (Hybrid)	विचिीय धोखाधड़ी, डेटा चोरी, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ((CII)) पर प्रायोजित साइबर हमले

2. आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां: क्षेत्रवार वर्गीकरण

सामरिक क्षेत्र	प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां एवं विधिक संवेदनशीलता
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख	नियंत्रण रेखा ((LoC)) से घुसपैठ, सीमा-पार गोलाबारी, छद्म युद्ध व लक्षित आतंकी हमले
मध्य व पूर्वी भारत	छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के घने वन; विकास व सरेंडर-पुनर्वास नीतियों से 2026 में शांति स्थापित
पूर्वोत्तर सीमांत	भारत-म्यांमार सीमा की खुली व पर्वतीय प्रकृति, शरणार्थी समस्या व विद्रोही गुटों की शरणस्थली
पंजाब व पश्चिमी सीमा	ड्रोन आधारित अत्याधुनिक हथियार व हेरोइन तस्करी, सीमा सुरक्षा ग्रिड व रात्रिकालीन निगरानी

3. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) एवं विशिष्ट अधिदेश

बल का नाम (CAPF)	प्राथमिक दायित्व, सीमा एवं परिचालन क्षेत्र
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)	भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल; आंतरिक सुरक्षा, नक्सल-रोधी अभियान, दंगा नियंत्रण व चुनाव सुरक्षा
सीमा सुरक्षा बल (BSF)	भारत-पाक एवं भारत-बांग्लादेश सीमा की रक्षा; 'रक्षा की प्रथम पंक्ति (First Line of Defence)'
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)	नागरिक हवाई अड्डों, परमाणु/अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो व प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)	भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा ((LAC)) की रक्षा; लद्दाख से अरुणाचल तक उच्च तुंगता में विशेषज्ञ बल
सशस्त्र सीमा बल (SSB)	भारत-नेपाल एवं भारत-भूटान की खुली व मैत्रीपूर्ण सीमाओं की चौकसी, जन-संपर्क व अनधिकृत आवाजाही रोकथाम
असम राइफल्स (Assam Rifles)	भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल (1835); भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा व पूर्वोत्तर में उग्रवाद-रोधी कमान
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)	गृह मंत्रालय अधीन विशेष आतंकवाद-रोधी कमांडो दस्ता (ब्लैक कैट); विमान अपहरण व बंधक संकट रोधी बल

आंतरिक बनाम बाह्य सुरक्षा भेद: सेना रक्षा मंत्रालय अधीन बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ((CAPF)) गृह मंत्रालय अधीन संघ सूची (प्रविष्टि 2A) व राज्य सूची (प्रविष्टि 1-2) के तहत सीमा चौकसी व आंतरिक शांति संभालते हैं।

4. प्रमुख खुफिया, सुरक्षा एवं अन्वेषण एजेंसियां

सुरक्षा / खुफिया एजेंसी	स्थापना, विधिक आधार एवं प्रमुख कार्य
आसूचना ब्यूरो (IB)	1887/1947; गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्राथमिक आंतरिक खुफिया एजेंसी; काउंटर-इंटेलिजेंस व आतंकवाद इनपुट
अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (RAW)	1968 (रामेश्वर नाथ काव); कैबिनेट सचिवालय अधीन बाह्य खुफिया, सामरिक विश्लेषण व राष्ट्रीय हित संरक्षण
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)	2008 ((NIA) अधिनियम 2008, 26/11 उपरांत); आतंकवाद व आतंकी फंडिंग पर राष्ट्रव्यापी अधिकारिता; 2019 संशोधन से विदेशी अधिकारिता
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)	1998; त्रि-स्तरीय ढांचा (शीर्ष परिषद, सामरिक नीति समूह, (NSAB)); अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सचिवालय प्रमुख (NSA)
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)	2004; राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ((NSA)) के सीधे अधीन तकनीकी खुफिया (उपग्रह इमेजिंग, साइबर ट्रैकिंग) एजेंसी

5. साइबर सुरक्षा अवसंरचना एवं I4C प्रणाली

साइबर सुरक्षा पहल	संस्थागत तंत्र एवं 2026 तक की प्रगति
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)	गृह मंत्रालय की शीर्ष संस्था; राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ((NCRP)) व अनुसंधान का संचालन
हेल्पलाइन 1930 एवं (CFCFRMS)	साइबर विचिीय धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रणाली; जून 2026 तक ₹11,158 करोड़ से अधिक की राशि सुरक्षित की गई
साइबर हॉटस्पॉट समन्वय टीमें	सर्वाधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले चिन्हित क्षेत्रों में 7 संयुक्त साइबर समन्वय टीमें सक्रिय व तैनात
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग	पोर्टल पर 2026 तक लगभग 53 लाख साइबर अपराध शिकायतें दर्ज व त्वरित निस्तारित की गईं

6. आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियां

प्रबंधन आयाम	विधिक, संस्थागत व सामरिक चुनौतियां
संघवाद व केंद्र-राज्य समन्वय	7वीं अनुसूची में 'पुलिस' व 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची में होने से केंद्रीय बलों की तैनाती पर समन्वय संकट
बहुआयामी विषम सीमा प्रबंधन	15,106 किमी स्थलीय सीमा पर नदीय, दलदली (कच्छ), हिमाच्छादित व पर्वतीय विषमताओं से स्मार्ट फेंसिंग चुनौती
असममित व संकर (Hybrid)	ड्रोन द्वारा सीमा-पार नशीले पदार्थों/हथियारों की आपूर्ति, डीपफेक व डिजिटल दुष्प्रचार से सामाजिक सौहार्द भंग
मानव संसाधन एवं तनाव प्रबंधन	अर्धसैनिक बलों में पदोन्नति विसंगतियां, दुर्गम तैनाती जनित कार्य तनाव, अत्याधुनिक हथियारों व प्रशिक्षण का अभाव

7. पुलिस सुधार एवं प्रकाश सिंह वाद (2006) के निर्देश

सुधार का क्षेत्र	उच्चतम न्यायालय के 7 ऐतिहासिक निर्देश ((Prakash Singh 2006))
राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission)	पुलिस पर अनुचित राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव रोकने व नीति निर्माण हेतु प्रत्येक राज्य में आयोग
(DGP) व अधिकारियों का कार्यकाल	(DGP) का चयन पारदर्शी समिति द्वारा व न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल; (SP)/(SHO) का भी न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल
कार्य का पृथक्करण	दैनिक कानून-व्यवस्था ((Law & Order)) तथा अपराध अनुसंधान ((Investigation)) विंग का स्पष्ट पृथक्करण
पुलिस जवाबदेही आयोग (PCA)	हिरासत में हिंसा, भ्रष्टाचार व गंभीर दुर्व्यवहार की जांच हेतु राज्य व जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण

आंतरिक सुरक्षा का समन्वित मॉडल: 'सुरक्षा + विकास + तकनीक + जनभागीदारी' — 31 मार्च 2026 को देश के सभी जिलों को (LWE) मुक्त करने में सफलता मिली। इसी समन्वित मॉडल से स्मार्ट फेंसिंग, (I4C), पुलिस सुधार व खुफिया सूचना आदान-प्रदान द्वारा संकर व साइबर युद्ध से निपटा जा सकता है।